भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3987

उत्तर देने की तारीख - 18/08/2025

सोमवार, 27 श्रावण, 1947 (शक)

मोबाइल स्किल वैन की स्थिति

†3987. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान सरकार समर्थित योजनाओं के अंतर्गत संचालित मोबाइल स्किल वैन की संख्या और मोबाइल स्किल वैन के माध्यम से प्रशिक्षित युवाओं की संख्या कितनी है तथा प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट या स्व-रोज़गार दर का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सीमित शारीरिक प्रशिक्षण केंद्रों वाले क्षेत्रों में अनुकूलित, सौर ऊर्जा चालित या इंटरनेट-क्षम स्किल वैन तैनात करने के लिए शुरू की गई पहलों का ब्यौरा क्या है और साथ ही मोबाइल प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को लागू करने के लिए राज्य कौशल विकास मिशनों (एसएसडीएम), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) भागीदारों और स्थानीय पंचायतों के साथ समन्वय तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) दूरस्थ, पर्वतीय, जनजातीय और अल्पसेवित क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उक्त वैन के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार स्थानीय उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट मोबाइल वैन विकसित करने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) : कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने विश्व बैंक ऋण सहायता प्राप्त केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना "आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अर्जन एवं ज्ञान जागरूकता (संकल्प)" को क्रियान्वित किया। यह स्कीम दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त हो गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य संस्थानों के सुदृढ़ीकरण, बाज़ार संपर्क में सुधार लाकर और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के समावेशन को बढ़ावा देकर अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता और स्तर को बढ़ाना था।

संकल्प स्कीम के अंतर्गत, एमएसडीई ने स्थानीय उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूरस्थ, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए मोबाइल कौशल इकाइयों को विकसित करने हेतु राज्य कौशल विकास मिशनों को समर्थन दिया है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य	मोबाइल स्किल यूनिट/वैनों की संख्या	पिछले 5 वर्षों में प्रशिक्षित युवाओं की संख्या
बिहार	1	3,388
कर्नाटक	2	284
नागालैंड	5	1,000
तमिलनाडु	1	178

इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर ने "कौशल वाहन" पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य खासकर ग्रामीण और भौगोलिक रूप से अलग-थलग पड़े क्षेत्रों में कौशल विकास में सूचना और पहुँच की कमी को पाटना है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहलों के माध्यम से, सीमित प्रशिक्षण अवसंरचना वाले क्षेत्रों में सौर ऊर्जा युक्त और इंटरनेट-आधारित इकाइयों सहित 23 विशेष रूप तैयार किए गए कौशल रथ और वैन लगाए गए हैं। स्किल ऑन व्हील्स और सोलर कम्युनिटी हब जैसी परियोजनाओं के तहत ये रथ और वैन संचालित होते हैं, जो दूरस्थ और अल्पसेवित क्षेत्रों में अल्पकालिक प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इन पहलों के तहत, 2.14 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

*****